



बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर

राजनीति विज्ञान विभाग एवं लोक प्रशासन विभाग के

संयुक्त तत्वावधान में

भगतसिंह, सुखदेव एवं राजगुरु

की शहादत की याद में आयोजित

दो दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सादर आमंत्रित हैं।

विषय : साझी शहादत - साझी विरासत एवं मौजूदा भारत

दिनांक 23-24 मार्च 2021, प्रातः 10:30 बजे से

उद्घाटन सत्र : 23 मार्च 2021 (10:30 से 1:30 बजे तक)

श्री टीकाराम जूली, श्रम राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार (मुख्य अतिथि)

प्रो. आनंद कुमार, प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं पूर्व प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रो. शम्सुल इस्लाम, प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री, जन नाट्यकर्मी एवं पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

श्री अनिल चमड़िया, प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक

प्रथम सत्र : 23 मार्च 2021 (2:00 से 4:30 बजे तक)

स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक धाराये : दर्शन व मूल्य

डॉ. स्त्री नूरयन्ती, पूर्व आयुक्त, इण्डोनेशियन जनरल इलेक्शन कमीशन एवं प्रोफेसर, रिसर्च सेन्टर फॉर पोलोटिकल स्टडीज, इण्डोनेशियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्सेज, जकार्ता (इण्डोनेशिया)

डॉ. आलोक श्रीवास्तव, प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री एवं परीक्षा नियंत्रक, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार वि. विद्यालय, जयपुर सारिका जैथलिया, जवाहर लाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जकार्ता (इण्डोनेशिया)

डॉ. हरित कुमार, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)

द्वितीय सत्र : 24 मार्च 2021 (11:00 से 12:30 बजे तक)

स्वतंत्रता आंदोलन की उपनिवेशवाद विरोधी चेतना एवं तात्कालिक साहित्य

डॉ. अनन्त भटनागर, प्रसिद्ध साहित्यकार, पूर्व प्राचार्य एवं महासचिव पीयूसीएल, राजस्थान (राज.)

प्रो. हेमेन्द्र चण्डालिया, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, जनार्दन राय नागर श्रमजीवी विद्यापीठ, उदयपुर (राज.)

डॉ. पयोद जोशी, सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, एम.एल.वी. कॉलेज, भीलवाड़ा (राज.)

डॉ. सुमन मौर्य, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

तृतीय सत्र : 24 मार्च 2021 (12:30 से 2:30 बजे तक)

भारत की राजनीतिक - प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था एवं लोक जीवन : आजादी से पूर्व व पश्चात

प्रो. मोहिन्द्र सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (पूर्व), लोक प्रशासन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरि.)

डॉ. धर्मेन्द्र मिश्रा, सह-आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, एस.एम.एम. राज. कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.)

डॉ. जनक सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

समापन सत्र (3:00 से 5:00 बजे तक)

श्रीमती सफिया जुबेर, माननीया विधायक, रामगढ़, राजस्थान विधानसभा, जयपुर (राज.) - मुख्य अतिथि

प्रो. राम पुनियानी, प्रसिद्ध चिन्तक, लेखक एवं पूर्व प्रोफेसर, आई.आई.टी. मुंबई (महाराष्ट्र)

प्रो. जे.पी. यादव, कुलपति, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (राज.)

अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी : 23 - 24 मार्च 2021

साझी शहादत - साझी विरासत एवं मौजूदा भारत

भारत की आजादी का आंदोलन न केवल अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी प्राप्त करने का आंदोलन था, बल्कि भारत के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पुनरुद्धार का साझा प्रयास भी था, जिसके लिए देश के सभी क्षेत्रों के सभी संप्रदायों, वर्गों, जातीय, भाषाई समूहों ने अपनी साझी शहादत दी है। इस साझा प्रयास में 1857 की क्रान्ति और उससे पूर्व के अनेक असंगठित आंदोलन तो शामिल हैं ही, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके नेतृत्व में प्रारंभ संगठित आंदोलन, जिसमें अनेक वैचारिक धारायें एक साथ काम कर रही थी, के साथ-साथ क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद की धारा, वामपंथी धारा, सामाजिक न्याय की धारा, आजाद हिन्द सेना इत्यादि के माध्यम से भी आजादी के आंदोलन को नई उर्जा और दिशा प्राप्त हुई। आजादी के आंदोलन में महिलाओं, किसानों, मजदूरों, दलित और आदिवासियों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। इस प्रकार आजादी के आंदोलन के मूल्य हमारी साझी शहादत से प्राप्त साझी विरासत है।

देश की आजादी के बाद इस साझी विरासत के मूल्यों का समावेश भारत के संविधान में भी किया गया है। संविधान में उल्लिखित लक्ष्य व मूल्य, जैसे समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध कराना तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता का निर्माण करना राज्य का दायित्व तो है ही, हम सभी नागरिकों का साझा संकल्प भी है। इस संकल्प के तहत भारतीय राज्य के सामने राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण, अर्थव्यवस्था का निर्माण और नागरिकों का निर्माण करने का लक्ष्य महत्वपूर्ण दायित्व था। अतः इन साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में आजाद भारत की पहली सरकार ने एक साथ पांच लक्ष्यों पर कार्य प्रारंभ किया - (1) वितरणात्मक न्याय के साथ आर्थिक विकास (2) समतावादी समाज का निर्माण (3) राजनीति, शिक्षा और नागरिक गतिविधियों का धर्मनिरपेक्षीकरण (4) राजनीति और संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण और (5) राष्ट्रीय एकीकरण करना।

उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हुए अनेक उतार चढ़ावों के साथ भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। किन्तु हम देखते हैं कि देश में 1991 में शुरू हुई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने से पूर्व ही हमारी राजनीतिक - प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा में दूरगामी बदलाव आ गया है। आजादी के दर्शन और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बाजारवादी राजनीतिक - सामाजिक संस्कृति ने महत्व प्राप्त कर लिया है, जहां मुनाफा ही एकमात्र मूल्य है। परिणामस्वरूप भारत में पिछले 25-30 वर्षों में लोक कल्याणकारी राज्य व लोक कल्याणकारी प्रशासन की अवधारणा तेजी से कमजोर हो रही है। संविदाकरण व आउट सोर्सिंग के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र को ही समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन में लैटरल एंट्री ने तो प्रशासनिक भर्ती में लोकतांत्रिक अधिकारों को ही खत्म कर दिया है। आम भारतीय अब यह मेहसूस करता है कि राष्ट्रीय कार्पोरेट और सत्ता के बढ़ते निरंकुश गठबंधन ने स्वतंत्रता आंदोलन की साझी विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों के सामने गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। परिणामस्वरूप हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक अधिकारों व जन आंदोलनों के लिए स्पेस खत्म होता जा रहा है। मौजूदा समय में देश के किसान अपनी खेती को बचाने के लिए सौ दिन से ज्यादा समय से आंदोलनरत हैं। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया है। सत्ता से पृथक राय रखने वाले नागरिकों को देशद्रोही बताकर खारिज कर दिया जाता है। व्यवस्था से खारिज यह वही व्यक्ति है जिसे संविधान में "हम भारत के लोग" के रूप में सबसे पहले जगह दी गई है और उसी ने भारत के संविधान को अंगिकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है।

इस परिप्रेक्ष्य में संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य यही है कि आजादी के जिन मूल्यों के लिए भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा असंख्य भारतीयों ने अपनी साझी शहादत दी थी, उसका स्मरण करते हुए हम मौजूदा भारत के हालातों पर चिंतन-मंथन करें, ताकि भटकाव के दौर से मुक्त होकर हम प्रगतिशील दिशा की तरफ बढ़ सकें।

संगोष्ठी में प्रतिभागियों से पत्र वाचन करवाया जायेगा, अतः निम्न विषयों पर शोधपत्र आमन्त्रित हैं।

1. स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक धारायें : दर्शन व मूल्य
 - ❖ 1857 की क्रांति व पूर्ववर्ती आंदोलनों की भूमिका
 - ❖ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका
 - ❖ क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद की धारा एवं हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की भूमिका
 - ❖ वामपंथी धारा की भूमिका
 - ❖ आजाद हिंद सेना की भूमिका
 - ❖ सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष : महिला, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी आंदोलनों की भूमिका
 - ❖ प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों की भूमिका
2. स्वाधीनता आंदोलन में उपनिवेशवाद विरोधी चेतना एवं तात्कालिक साहित्य
3. भारती की राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था एवं लोक जीवन : आजादी से पूर्व व पश्चात्
 - ❖ ब्रिटिश राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था का भारतीय लोक जीवन पर प्रभाव
 - ❖ स्वाधीनता आंदोलन का ब्रिटिश राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव
 - ❖ आजादी पश्चात् लोक कल्याणकारी राज्य व प्रशासन : उदरीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण का प्रभाव
 - ❖ मौजूदा भारतीय लोकतंत्र तथा आजादी की साझी विरासत : दशा व दिशा

नोट:-

1. अन्तर राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहभागिता करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
2. संगोष्ठी में शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले सभी प्रतिभागी अपने शोध पत्र का सारांश दिनांक 21 मार्च 2021 तक webinarsartscollege@gmail.com ईमेल पर अनिवार्य रूप से मेल कर दें।
3. दिनांक 21 मार्च 2021 तक मेल करने वाले प्रतिभागियों को ही पत्र वाचन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. पंजीकरण की अंतिम तिथि दिनांक 21 मार्च 2021 निर्धारित की गई है।
5. पंजीकरण करवाने वाले प्रतिभागियों को सहभागिता हेतु जूम लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा।
6. शोध पत्रों का प्रकाशन ISBN पुस्तक में कराया जाना प्रस्तावित है। अपने शोध पत्र webinarsartscollege@gmail.com पर ईमेल करें।



आयोजन समिति

डॉ. रेखा शर्मा
प्राचार्य एवं संरक्षक

डॉ. रमेश बैरवा
संयोजक
मो. 8209780345

डॉ. महेश गोठवाल
समन्वयक
मो. 9414051465

डॉ. भरत मीणा
आयोजन सचिव
मो. 9252721190

डॉ. कर्मवीर सिंह
सह-संयोजक

डॉ. रेणु मित्तल
सह-संयोजक

राजेश गुप्ता
सह-आयोजन सचिव

एम.पी. बाँयला
सदस्य

डॉ. शीतल मीणा
सदस्य

डॉ. सुनीता मीणा
सदस्य

नन्दराम खटीक
सदस्य

डॉ. गुलाब बाई
सदस्य

कौशल कुमार
सदस्य

एन. राजेन्द्र सिंह
सदस्य

डॉ. विनय पिंजानी
सदस्य

डॉ. अग्नि देव
सदस्य

डॉ. सुरेन्द्र सिंह चौधरी
सदस्य

महाविद्यालय परिचय

अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित ऐतिहासिक शहर अलवर ने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति दिखाई है। अलवर के महाराजा जयसिंह ने साधारण जन को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर 1930 में राजर्षि महाविद्यालय की स्थापना। वर्ष 1979 में राजर्षि महाविद्यालय का विभाजन करके कला और कानून संकायों के साथ राजकीय कला महाविद्यालय की स्थापना की गई। वर्ष 1999 में राजकीय कला महाविद्यालय का नाम परिवर्तित करके बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय किया गया। बाबू शोभाराम मेवात क्षेत्र के महान व्यक्तित्व रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सफलतापूर्वक प्रजामंडल आंदोलन का संचालन किया था। वे मत्स्य संघ के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं।

वर्तमान में बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय राज्य की महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में उभर कर सामने आया है। अलवर के मेवात क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द्र और साझी संस्कृति - साझी विरासत की परंपरा रही है। इस साझी विरासत की ताकत भविष्य में निश्चित रूप से देश के शैक्षणिक संस्थानों में इस महाविद्यालय को निश्चित रूप से उच्च स्थान सुनिश्चित कराएगी, जहां विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुलभ होगी। इस महाविद्यालय में 8 विषयों में स्नातकोत्तर एवं 10 विषयों में स्नातक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें लगभग 5000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय में मानविकी और समाज विज्ञान के 10 विषयों में शोध अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय ने कोरोना काल में विविध विषयों राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के आयोजनों के साथ आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के संयुक्त तत्वावधान में तीन विषयों में ज्ञान गंगा कार्यक्रम (फैकल्टी डेवलेपमेन्ट कार्यक्रम) का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

पंजीकरण लिंक :-



पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें